

उद्यम पंजीकरण लेने के लाभ

भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राजपत्र के माध्यम से भारत, असाधारण, भाग- II, खंड - 3, उप-खंड (ii), दिनांक 26 जून, 2020 अधिसूचित उद्यमों को वर्गीकृत करने के लिए निवेश और टर्नओवर दोनों से युक्त समग्र मानदंड सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम 1 जुलाई, 2020 से प्रभावी हैं।

एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुरूप और करने में आसानी के लिए व्यवसाय, यह प्रणाली एमएसएमई को स्थायी पंजीकरण यानी 'उद्यम पंजीकरण' के लिए मदद करेगी।

मुख्य विशेषताएं:

1. कोई भी व्यक्ति उद्यम के लिए उद्यम पंजीकरण प्राप्त कर सकता है। इसके माध्यम से पंजीकृत किया जा सकता है पोर्टल यानी <https://udyamregistration.gov.in/Government-India/MinistryMSMEregistration.htm>
2. उद्यम पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस है। कोई भी दस्तावेज अपलोड करने की इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है।
3. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। किसी को कोई लागत या शुल्क नहीं देना है।
4. पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के बाद एक ई-प्रमाण पत्र, अर्थात् "उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र" ऑनलाइन जारी किया जाएगा।
5. इस प्रमाणपत्र में एक गतिशील क्यूआर कोड है जिससे हमारे पोर्टल पर वेब पेज और विवरण (उद्यम के बारे में) पहुँचा जा सकता है।
6. जो कोई भी स्व-घोषित तथ्यों को जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करता है या दबाने का प्रयास करता है और उद्यम पंजीकरण या अपडेशन प्रक्रिया में प्रदर्शित होने वाले आंकड़े इसके अधिनियम की धारा 27 के तहत निर्दिष्ट दंड लिए उत्तरदायी होंगे।
7. ऑनलाइन प्रणाली पूरी तरह से आयकर और माल और सेवा कर के साथ एकीकृत है पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) प्रणाली, निवेश और उद्यमों के कारोबार का विवरण सरकारी डेटाबेस से स्वचालित रूप से लिया जाता है। निर्यात को टर्नओवर गणना के हिस्से के रूप में नहीं लिया जाता है।
8. जिनके पास EM-II या UAM पंजीकरण या किसी प्राधिकरण द्वारा जारी कोई अन्य पंजीकरण है एमएसएमई-मंत्रालय के तहत 31.12.2021 से पहले खुद को फिर से पंजीकृत करना होगा।
9. कोई भी उद्यम एक से अधिक उद्यम पंजीकरण दाखिल नहीं करेगा। हालाँकि, किसी भी संख्या में विनिर्माण या सेवा या दोनों सहित गतिविधियों को एक पंजीकरण में निर्दिष्ट या जोड़ा जा सकता है।

पंजीकरण की आवश्यकता:

- रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ आधार नंबर ही काफी है।
- 01.04.2021 से पैन और जीएसटी नंबर होना अनिवार्य है।

इस पंजीकरण के लाभ:

1. यह एक उद्यम के लिए एक स्थायी पंजीकरण और मूल पहचान संख्या होगी।
2. एमएसएमई पंजीकरण पेपरलेस है और स्व-घोषणा पर आधारित है।
3. पंजीकरण के नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
4. विनिर्माण या सेवा या दोनों सहित गतिविधियों की कोई भी संख्या निर्दिष्ट की जा सकती है या एक पंजीकरण में जोड़ा गया। उद्यम पंजीकरण के साथ, स्वयं GeM (सरकारी ई-मार्केट प्लेस, G से B के लिए एक पोर्टल) और समाधान पोर्टल पर (भुगतान में देरी से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक पोर्टल) उद्यम पंजीकरण कर सकते हैं और साथ ही साथ एमएसएमई खुद भी TReDS प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड हो सकते हैं (प्राप्तियों के इनवॉइस पर कारोबार किया जाता है यह मंच) तीन उपलब्ध प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अर्थात् (1) www.invoicemart.com (2) www.m1xchange.com (3) www.rxil.in।

5. उद्यम पंजीकरण एमएसएमई को की योजनाओं का लाभ उठाने में भी मदद कर सकता है एमएसएमई मंत्रालय जैसे क्रेडिट गारंटी योजना, सार्वजनिक खरीद नीति, अतिरिक्त सरकारी निविदाओं में बढ़त और विलंबित भुगतान आदि से सुरक्षा।
6. बैंकों से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के पात्र बनें।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार:

प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) दिशानिर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। आरबीआई ने प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के संबंध में अपने परिपत्र सं. आरबीआई/एफआईडीडी/2020-21/72मास्टरदिशा-निर्देश FIDD.CO.Plan.BC.5/04.09.01/2020-21दिनांक 04 सितंबर, 2020 (29 अप्रैल, 2021 तक अद्यतन)। तदनुसार, प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत श्रेणियां हैं (i) कृषि (ii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (iii) निर्यात ऋण (iv) शिक्षा (v) आवास (vi) सामाजिक आधारभूत संरचना (vii) अक्षय ऊर्जा (viii) अन्य। इसलिए, एमएसएमई क्षेत्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के अंतर्गत आता है। आरबीआई के अनुसार, एमएसएमई की परिभाषा भारत सरकार (जीओआई), राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. के अनुसार होगी। 2119 (ई) दिनांक 26 जून, 2020 का परिपत्र आरबीआई/2020-2021/10-एफआईडीडी.एमएसएमई और एनएफएस.बीसी.सं.3/06.02.31/2020-21 के साथ पठित एफआईडीडी.एमएसएमई और एनएफएस के साथ पठित। ई.पू. क्रमांक 4/ 06.02.31/2020-21 दिनांक 2 जुलाई, 2020, 21 अगस्त, 2020 क्रमशः 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह' पर और समय-समय पर अद्यतन किया गया। इसके अलावा, ऐसे एमएसएमई उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी उद्योग से संबंधित किसी भी तरीके से माल के निर्माण या उत्पादन में लगे होने चाहिए या किसी सेवा या सेवाओं को प्रदान करने या प्रदान करने में लगे हुए होने चाहिए।

आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एमएसएमई को दिए गए सभी बैंक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण के तहत वर्गीकरण के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं

Benefits of taking Udyam Registration

The Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises vide Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section – 3, Sub-Section (ii), dated the 26th June, 2020 notified composite criteria consisting of both investment and turnover for classifying the enterprises as Micro, Small and Medium Enterprises with effect from the 1st day of July, 2020.

In order to conform to the new definition of MSMEs and to facilitate the ease of doing business, this system would help MSMEs for a permanent Registration i.e. 'Udyam Registration'.

Salient Features:

- Anyone may obtain the Udyam Registration for the enterprise. It can be registered through the portal i.e. <https://udyamregistration.gov.in/Government-India/MinistryMSME-registration.htm>
- The process for Udyam Registration is fully digitalized and paperless. There is no need to upload any document.
- The registration process is totally free. No Costs or Fees are to be paid to anyone.
- An e-certificate, namely, "Udyam Registration Certificate" shall be issued online on completion of the registration process.
- This certificate has a dynamic QR Code from which the web page on our Portal and details about the enterprise can be accessed.
- Whoever intentionally misrepresents or attempts to suppress the self-declared facts and figures appearing in the Udyam Registration or updation process shall be liable to such penalty as specified under section 27 of the Act.
- The online system is fully integrated with Income Tax and Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) systems, details on investment and turnover of enterprises are taken automatically from Government data bases. Exports are not taken as part of turnover calculation.
- Those who have EM-II or UAM registration or any other registration issued by any authority under the Ministry of MSME, will have to re-register themselves before 31.12.2021.
- No enterprise shall file more than one Udyam Registration. However, any number of activities including manufacturing or service or both may be specified or added in one Registration.

Requirement of Registration:

- Only Aadhar Number is enough for registration.
- Having PAN & GST number is mandatory from 01.04.2021.

Benefits of this registration:

- It will be a permanent registration and basic identification number for an enterprise.
- MSME Registration is paperless and based on self-declaration.
- There will be no need for renewal of Registration.
- Any number of activities including manufacturing or service or both may be specified or added in one Registration. Along with the Udyam Registration, Enterprises may register

themselves on GeM (Government e-Market Place, a portal for G to B) & SAMADHAAN Portal (a portal to address issues relating to delay in payments) and simultaneously MSMEs themselves can also onboard on TReDS Platform (the invoices of receivables are traded on this platform) through three available platforms i.e. (a) www.invoicemart.com (b) www.m1xchange.com (c) www.rxil.in ".

- The Udyam Registration may also help MSMEs in availing the benefits of Schemes of Ministry of MSMEs such as Credit Guarantee Scheme, Public Procurement Policy, additional edge in Government Tenders & Protection against delayed payments, etc.
- Become eligible for priority sector lending from Banks.

Priority Sector Lending:

The Priority Sector Lending (PSL) guidelines are issued by Reserve Bank of India. RBI has issued guidelines on Priority Sector Lending vide its circular no. RBI/FIDD/2020- 21/72 Master Directions FIDD.CO.Plan.BC.5/04.09.01/2020-21 dated September 04, 2020 (updated as on April 29, 2021). Accordingly, the categories under priority sector are (i) Agriculture (ii) Micro, Small and Medium Enterprises (iii) Export Credit (iv) Education (v) Housing (vi) Social Infrastructure (vii) Renewable Energy (viii) Others. Therefore, MSME Sector falls under Priority Sector Lending. As per RBI, the definition of MSMEs will be as per Government of India (GoI), Gazette Notification S.O. 2119 (E) dated June 26, 2020 read with circular RBI/2020-2021/10-FIDD.MSME & NFS.BC.No.3/06.02.31/2020-21 read with FIDD.MSME & NFS. BC. No.4/ 06.02.31/2020-21 dated July 2, 2020, August 21, 2020 respectively on 'Credit flow to Micro, Small and Medium Enterprises Sector' and updated from time to time. Further, such MSMEs should be engaged in the manufacture or production of goods, in any manner, pertaining to any industry specified in the First Schedule to the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 or engaged in providing or rendering of any service or services.

All bank loans to MSMEs conforming to the RBI guidelines qualify for classification under priority sector lending.

ઉદ્યમ નોંધણી લેવાના ફાયદા

સૂક્ષ્મ, નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો મંત્રાલય, ભારત સરકાર, ભારતના રાજપત્ર (ગેઝેટ), અસાધારણ, ભાગ -2, વિભાગ-3, ઉપ-વિભાગ (2) ના, તારિખ 26 મી જૂન, 2020 ના દિવસેથી સૂક્ષ્મ, નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગોને રોકાણ અને ટર્નઓવર ના સંયુક્ત માપદંડને આધારિત વર્ગીકૃત કરવા સુચિત કરવામાં આવ્યા જે તારિખ 1 જુલાઈ, 2020 થી અમલમાં આવેલ છે.

આ રાજપત્રિય સુચના નવા સૂક્ષ્મ, નાના અને મધ્યમ એકમોને વ્યવસાયમાં સરળતા માટે "ઉદ્યમ નોંધણી" એ કાયમી નોંધણીની સુવીધા આપે છે.

મુખ્ય લક્ષણો:

- કોઈપણ વ્યક્તિ એન્ટરપ્રાઇઝ માટે ઉદ્યમ નોંધણી મેળવી શકે છે. તે પોર્ટલ એટલે કે

<https://udyamregistration.gov.in>

અથવા

Government-India/MinistryMSME- registration.htm

વેબ પેજ દ્વારા નોંધણી કરાવી શકે છે.

- ઉદ્યમ નોંધણી માટેની પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે ડિજિટલાઇઝ્ડ અને પેપરલેસ છે. તે વેબ પેજ ઉપર કોઈપણ દસ્તાવેજ અપલોડ કરવાની જરૂર નથી.
- નોંધણી પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે મફત છે. કોઈને કોઈ ખર્ચ કે ફી ચૂકવવાની નથી.
- ઈ-સર્ટિફિકેટ નું નામ "ઉદ્યમ નોંધણી પ્રમાણપત્ર" છે. જે ઓનલાઇન નોંધણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ ઓનલાઇન જારી કરવામાં આવશે.
- આ પ્રમાણપત્રમાં એક ગતિશીલ QR કોડ છે. જેમાંથી અમારા પોર્ટલ પરનું વેબ પેજ અને એન્ટરપ્રાઇઝ વિશેની વિગતો મેળવી શકાય છે.
- જેઓ, જેણે ઉદ્યમ નોંધણી અથવા અપડેશન પ્રક્રિયામાં દેખાતા સ્વ-પ્રમાણિત જાહેર કરેલા તથ્યો અને આંકડાઓને બદલ ઇરાદાપૂર્વક ખોટી રીતે રજૂ કર્યા નો પ્રયાસ કર્યો હોય તે કાયદાની કલમ 27 હેઠળ નિર્દિષ્ટ દંડ માટે જવાબદાર રહેશે.
- આ ઓનલાઇન સિસ્ટમ (ઈન્કમ ટેક્સ) આવક વેરા અને ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર (GSTIN) સિસ્ટમ સાથે સંપૂર્ણ રીતે સ્વ-સંકલિત છે, ઉદ્યમના રોકાણ અને સાહસોના ટર્નઓવરની વિગતો સરકારી ડેટા બેઝમાંથી આપમેળે લેવામાં આવે છે. ઉદ્યમના નિકાસની(Export) વીગતો કુલ વેચાણ (ટર્નઓવર) ના ભાગરૂપે લેવામાં આવતી નથી.
- એવી વ્યક્તિઓ કે યુનિટ કે જેમની પાસે "EM-II" અથવા "UAM" રજીસ્ટ્રેશન છે અથવા MSME મંત્રાલય હેઠળની કોઈપણ સત્તા દ્વારા જારી કરાયેલ અન્ય કોઈ નોંધણી છે, તેઓએ 31.12.2021 પહેલા ફરીથી નોંધણી કરાવવી પડશે.
- કોઈ પણ ઉદ્યમ (એન્ટરપ્રાઇઝ) એક કરતા વધારે "ઉદ્યમ પ્રમાણપત્ર" મેળવી શકશે નહીં. જો કે, કોઈ પણ ઉદ્યમ ઉત્પાદન અથવા સેવા અથવા બંને સહિતની કોઈપણ એક પ્રવૃત્તિ માટે નોંધણી કરાવી શકશે.

નોંધણીની આવશ્યકતા:

- નોંધણી માટે માત્ર આધાર નંબર જ પૂરતો છે.

- તારીખ 1 વી એપ્રિલ 2021, બાદ પાંન નંબર(PAN CARD) અને GST નંબર ઉદ્યમ નોંધણી માટે ફરજિયાત છે.

આ નોંધણીના લાભો:

- ઉદ્યમ નોંધણી એ એકમો માટે મૂળભુત ઓળખ અને કાયમી નોંધણી નંબર હશે.
- એમ.એસ.એમ.ઇ.(ઉદ્યમ નોંધણી એ કાગળ વીના (PAPER LESS) અને સ્વ-ઘોષણા ની માહિતી પર આધારિત છે.
- આ નોંધણી (રજીસ્ટ્રેશન) માટે રિન્યુ કરવાની કોઈ જરૂર રહેશે નહીં.
- ઉદ્યમ એકમોની ઉત્પાદન અથવા સેવા અથવા બંને સહિતની કોઈપણ પ્રવૃત્તિઓ (એક અથવા એક થી વધારે) નોંધણીમાં ઉમેરી શકાય છે.
- ઉદ્યમ નોંધણીની સાથે સાથે એકમો સરકારી ઈ-માર્કેટ (GeM , G to B પોર્ટલ) અને સમાધાન પોર્ટલ (જેમાયુકવણીમાં વિલંબને લગતા મુદ્દાઓને ઉકેલવા માટેનું પોર્ટલ) અને સાથે સાથે એકમો પોતે પણ (TReDS) પ્લેટફોર્મ પર ઓનબોર્ડ કરી શકે છે.

આ પ્લેટફોર્મ દ્વારા એટલે કે:

(a) www.invoicemart.com

(b) www.m1xchange.com

(c) www.rxil.in " ઉપર જોઈ શકે છે.

- એકમો ને ઉદ્યમ નોંધણી દ્વારા એમ.એસ.એમ.ઇ. મંત્રાલયની યોજનાઓ જેમ કે ક્રેડિટ ગેરંટી યોજના, જાહેર પ્રાપ્તિ નીતિ, અને વધારામા સરકારી ટેન્ડર તથા વીલંબિત યુકવણીના કેસોમા વધારાની મદદ મેળવી શકે છે.
- નોંધાયેલા એકમો બેંકો પાસેથી અગ્રતા ક્ષેત્ર ધિરાણ માટે લાયક બને છે.

અગ્રતા ધિરાણ ક્ષેત્ર:

- ભારતીય રિઝર્વ બેંક દ્વારા પ્રાધાન્યતા ક્ષેત્ર ધિરાણ (PSL) માર્ગદર્શિકા જારી કરવામાં આવે છે. આથી આર.બી.આઇ. એ પ્રાધાન્યતા ક્ષેત્રના ધિરાણ અંગે તેના પરિપત્ર નં. RBI/FIDD/2020- 21/72, અને માસ્ટર દીશા નિર્દેશો (FIDD.CO.Plan.BC.5/04.09.01/2020-21, તારીખ 04 સપ્ટેમ્બર, 2020. (નવીનીકરન 29 એપ્રિલ, 2021 ના રોજથી.) તદનુસાર, અગ્રતા ક્ષેત્ર હેઠળની શ્રેણીઓ આ છે (i) કૃષિ (ii) સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (iii) નિકાસ ધિરાણ (iv) શિક્ષણ (v) આવાસ (vi) સામાજિક માળખાગત (vii) પુનઃ નવીનીકરણીય ઉર્જા (viii) અન્ય. એથી એમ.એસ.એમ.ઇ. સેક્ટર પ્રાધાન્યતા ક્ષેત્ર ધિરાણ હેઠળ આવે છે. આરબીઆઈ ના દીશા નિર્દેશો મુજબ ભારત સરકાર ના રાજપત્ર (Gazette Notification), [S.O. 2119(E) dated June – 26, 2020] ની સાથે વચવામા આવશે. પરિપત્ર [{RBI/2020-2021/10-FIDD.MSME & NFS.BC.No.3/06.02.31/2020-21 }સાથે {FIDD.MSME & NFS.BC. No.4/02.02.31/2020-21 dated July 2,2020, August 21, 2020 સાથે વાંચ્યું.}] આ પ્રમાને સૂક્ષ્મ,નાના અને મધ્યમ સાહસો ને ધિરાણ અને સમય સમય પર તેમા સુધારા થાય તે મુજબ. આગળ ઉપર આવા એમ.એસ.એમ.ઇ. સાહસો કોઈપણ રીતે વસ્તુના ઉત્પાદન અથવા ઉત્પાદનની પ્રક્રિયામા રોકાયેલા હોવા જોઈએ. અથવા કોઈપણ પ્રકારની સેવા અથવા સેવાઓ પૂરી પાડવા અથવા રજૂ કરવામાં રોકાયેલા હોવા જોઈએ. જે ઉદ્યોગો (વિકાસ અને નિયમિતતા) અધિનિયમ 1951 ની પ્રથમ સુચીમા ઉલ્લેખિત ઉદ્યોગો અંતર્ગત હોવા જોઈએ.

આથી આરબીઆઈ ની ગાઇડલાઇન મુજબ એમ.એસ.એમ.ઇ. સાહસો કોઈપણ બેંકની લોન

માટે અગ્રતા ક્ષેત્ર ધિરાણ વર્ગીકરણ માટે લાયક છે.